मीडिया समन्वयक कार्यालय

जामिया मिल्लिया इस्लामिया

विज्ञप्ति 27 अक्तूबर

ब्याज मुक्त बैंकिंग पर जामिया मिल्लिया में व्याख्यान

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अर्थशास्त्र विभाग में 'पूर्व छात्र व्याख्यान श्रृंखलामाला' के तहत ''ब्याज मुक्त बैंकिंग'' विषय पर चर्चा हुई। इसमें यह विचार रखा गया कि वित्तीय व्यवस्था को पूर्णतः समावेशी बनाने के लिए भारत में ब्याज मुक्त बैंकिंग का विकल्प भी होना चाहिए क्योंकि धार्मिक आस्थाओं के चलते देश के लगभग एक करोड़ लोग बैंकिंग सुविधाओं का लाभ नहीं उठाते हैं। ये लोग ब्याज को ''हराम'' मानते हैं।

भारत सरकार के कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के आर्थिक सलाहकार और 1981 बैच के जामिया मिल्लिया के छात्र रहे अर्थशास्त्री के. एम. मानिकफान आलिमअलमीगोथी ने विश्व बैंक का हवाला देते हुए कहा कि हमारे देश में धार्मिक आस्थाओं के चलते लगभग एक करोड़े से अधिक आबादी बैंकों से दूर रहती है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी आबादी के बहुत सारे देश हैं, इसलिए ब्याज को ''हराम'' मानने वाली देश के इस बड़ी आबादी के लिए 'ब्याज मुक्त बैंकिंग व्यवस्था'' होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि इन लगभग एक करोड़ लोगों का देश की वित्तीय व्यवस्था में समावेश कराने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो गया है।

श्री आलिमअलमीगोथी ने कहा कि पश्चिमी देशों में ब्याज मुक्त बैंकिंग के विचार ने काफी लोकप्रियता हासिल की है और लोग इस व्यवस्था से जुड़ने लगे

हैं। इस व्यवस्था से जुड़ने वाले लोग अपने बैंक के लाभ और हानि दोनों में शामिल होते हैं।

उन्होंने कहा कि ब्याज मुक्त बैंकिंग का एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है ऐसे बैंकों का धन समाज पर कुप्रभाव डालने वाले अश्लील साहित्य, मादक पदार्थों और शोषणकारी उद्यमों जैसे क्षेत्रों को वित्तपोषण के लिए नहीं दिया जा सकता है।

श्री आलिमअलमीगोथी ने कहा कि इन बातों को देखते हुए भारत में ब्याज मुक्त बैंकिंग की शुरूआत के बिना वित्तीय समावेशीकरण का काम अधूरा रहेगा।

इस अवसर पर अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख शाहिद अहमद और जेएमआई पूर्व छात्र गतिविधि विभाग के समन्वयक अशरफ इलियानी ने मंच साझा किया।

इस व्याख्यानमाला को सुनने के लिए बड़े पैमाने पर विभिन्न विभागों के अध्यापक और छात्र उपस्थित थे।

प्रो साइमा सईद

मीडिया कोऑर्डनैटर